Post Reg. No. - Jodhpur/442/2021-23
(Posting Date : 2-3/16-17 every month)

रजिस्ट्रेशन नम्बर RJHIN/2013/59770

पाक्षिक

महकता मरूधर

सच्चाई, राष्ट्रीयता, ईमानदारी व निर्भीकता का पक्षधर

वर्ष : 10 अंक : 11 जैसलमेर, 01 जून, 2023 मूल्य : 5 रूपये

अंजना पीसीसी सचिव मनोनित

जैसलमेर। पूर्व जिला प्रमुख व राज्य महिला आयोग सदस्या अंजना मेघवाल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव मनोनीत किया। अंजना मेघवाल के पीसीसी सचिव नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों में खुशी की लहर है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर, कृषि उपज मंडी मोहनगढ़ अध्यक्ष रुपचंद सोनी, कृषि उपज मंडी मोहनगढ़ उपाध्यक्ष रतनाराम भील, कांग्रेस कमेटी ब्लॉक जैसलमेर अध्यक्ष मालमसिंह, संगठन महामंत्री कमलेश छंगाणी, प्रवक्ता उपेंद्र आचार्य, सरपंच प्रतिनिधि बीदा लियाकत अली, सरपंच प्रतिनिधि कनोई यार मोहम्मद, जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य सुभान खां चानिया, बचल खां बासनपीर, कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष कंवराजसिंह जाम, पार्षद प्रतिनिधि गोरधनराम भील, अब्बास खान ने बधाई दी। इसके साथ ही बडी संख्या में जिलेवासियों ने पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव मनोनीत होने पर व्यक्तिगत तथा सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी। वहीं अंजना मेघवाल ने भी सभी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने किया ऐलान......

पहली 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज शुल्क भी किया माफ

जैसलमेर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के लोगों के लिए प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी राहत देगी। इन परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बातचीत के बाद मिले फीडबैक पर पाया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। सरकार को मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब पूर्ववत 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अब 100 यूनिट के बाद कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि जो परिवार 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करते हैं उनको पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इन शुल्कों का भुगतान राज्य सरकार करेगी।.

सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्तिको दबोचा, पूछताछ जारी

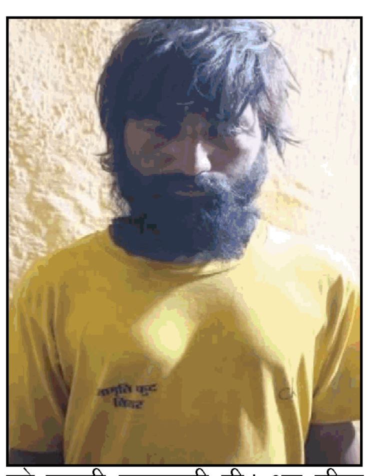

जैसलमेर। जिले से लगती भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार जिले के लूणार गाँव से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने युवक की पूरी तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान उस युवक के पास से कुछ भी संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुआ है। जिसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने उससे गहन पूछताछ की. पूछताछ में युवक ने अपना नाम दिलीप कुमार बताया है. जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है और वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला है। सरहद के प्रतिबंधित इलाके में पहुंचने को लेकर वो कुछ भी नहीं बोल पाया। जिस पर सीमा सुरक्षा बल के जवान उसे पकड़कर बटालियन लेकर आए और अपने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अब सीमा सुरक्षा बल उससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पहुँचने के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी है। शुरूआती पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति सीमा क्षेत्र में आने के कारणों की सही सही जानकारी नहीं दे पाया। बीएसएफ अपनी पूछताछ के बाद ही इसे सुरक्षा एजेंसियों को सुपुर्द किया है। अब सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से इस युवक से पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां उस युवक के यहां तक पहुंचने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल ने पहले भी अवांछनीय गतिविधियों को लेकर कई कार्रवाई की है। पूर्व में बॉर्डर के पास घूमते संदिग्धों सहित कई जासूसों को भी बीएसएफ ने धर दबोचा है।

सरहदी इलाका प्रतिबंधित

गौरतलब है कि भारत – पाकिस्तान सीमा के पास के इलाके प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। यहां बिना इजाजत के जाना मना है। अगर कोई सरहदी इलाके में बिना इजाजत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहां तक कि सरहदी इलाके के ग्रामीण भी सीमा के 5 किमी एरिया में बिना इजाजत के शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं घूम सकते हैं। ऐसे में किसी अन्य राज्यों के लोगों का सरहदी इलाकों में पकड़े जाने सुरक्षा में सेंध हो सकती है। सुरक्षा को लेकर सीमा सुरक्षा बल हमेशा सतर्क रहती है और अनजान लोगों को पकड़ कर पुलिस को सौंप देती है।

करीब 140 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया बन रहा जैसलमेर का रेलवे स्टेशन

जैसलमेर। करीब 140 करोड़ की लागत से जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का काम जोर शोर से जारी है। सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग की जगह अब डबल मंजिल की बिल्डिंग बनेगी जिसमें जैसलमेर के पीले पत्थर का उपयोग होगा। इस रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के पीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख पर्यटक स्थल होने के साथ–साथ सेना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे द्वारा जैसलमेर स्टेशन का 140 करोड़ रुपए से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इंटरनेशनल लेवल का पुनर्विकास किया जा रहा है। देशभर से जैसलमेर आने वाले सैलानियों को स्टेशन का विकास होने से कई आधुनिक सुविधाओं का एहसास मिलेगा। इसके साथ–साथ सेना के जवानों को अपने काम पर जाने और घर आदि जाने के लिए कई सुविधाएं मिलेगी।

पीले पत्थरों से बनेगी राजस्थानी हैरिटेज और मॉडर्न लुक की बिल्डिंग

कैप्टन शशि किरण के अनुसार एमडी विजय शर्मा के दिशा–निर्देशन में जैसलमेर स्टेशन के डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है। स्टेशन पर नई बिल्डिंग बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जैसलमेर स्टेशन की पुरानी स्टेशन बिल्डिंग को तोड़कर नई स्टेशन बिल्डिंग के लिये खुदाई का काम हो गया है। और बिल्डिंग कॉलम का काम जारी है। साथ ही नये पार्सल ऑफिस, एमसीओ ऑफिस का काम छत लेवल तक पूरा हो गया है। जैसलमेर स्टेशन पर लगभग 48 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। स्टेशन पर 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में मुख्य स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन के डेवलपमेंट में राजस्थानी हेरिटेज और मॉडर्न तरीके से इसे आकर्षक लुक दिया जाएगा।

शॉपिग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड कोर्ट शामिल

मुख्य स्टेशन बिल्डिंग में एंट्री व एग्जिट के लिए अलग–अलग गेट, 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में एयर कोनकॉर्स, कवर्ड प्लेटफार्म, लिफ्ट व ऐस्कलेटर की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज, मॉडर्न वेटिंग रूम, शॉपिग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज, बेस्ट लाइटिंग, फूड कोर्ट आदि बनेंगे। इसके साथ ही स्टेशन पर पार्किंग सुविधा, दिव्यांगजन के लिए अनुकूल सुविधाएं, संकेतक, शौचालय, बैगेज स्कैनर, मैटल डिटेक्टर और कोच गाइडेन्स बोर्ड व ट्रेन इन्डिकेटर आदि के साथ सभी प्रकार की मॉडर्न यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रीन बिल्डिंग आधारित सुविधाएं होगी

गोल्डन सिटी के नाम से विख्यात जैसलमेर शहर में स्थित जैसलमेर स्टेशन का पूरा डेवलपमेंट इसकी भव्यता और आकर्षक बिल्डिंग को देखने से नजर आएगा। स्टेशन के विकास में ऊर्जा खपत में कमी के लिए ग्रीन बिल्डिंग आधारित सुविधाएं होंगी, जो मॉडर्न ऊर्जा के साथ कचरे का उचित निपटारा, वर्षा जल संचयन आदि जैसे संसाधनों के साथ होगी। स्टेशन पर हरित और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।

जिले में अब तक 6 लाख 41 हजार 80 गारंटी कार्ड जारी, 1 लाख से अधिक परिवार हुए लाभान्वित

जैसलमेर। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप को जनता का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसलमेर जिले में अब तक 1 लाख 42 हजार 864 परिवारों को सरकार की 10 योजनाओं के 6 लाख 41 हजार 80 गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

बुधवार को वितरित किये 6 हजार 599 गारंटी कार्ड

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि बुधवार को कुल 6 हजार 599 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किये गए हैं। जिसमें से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 744, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 1105, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1105, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 94, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 502, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 1395, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 566, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 277, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 799, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 12 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए।

भारत–पाक सीमा से लगती हुई 5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में रात्रि प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

जैसलमेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डबी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत–पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में आगामी 12 जून 2023 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिए सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत–पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन–जीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाबी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, मोहरोवाला, मालासर तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्धा लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक वैध अनुमति–पत्र (जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश के अनुसार जिले में भारत–पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को यह सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं करें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 12 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा।

श्री हजूरी समाज संरक्षक मंडल एवं मुख्य प्रबंध कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित

जैसलमेर। श्री हजूरी समाज संरक्षक मंडल एवं मुख्य प्रबंध कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। समाज के मीडिया प्रभारी भीम सिंह पवार ने बताया कि अध्यक्ष कमलसिंह भाटी की अध्यक्षता में श्री हजूरी समाज संरक्षक मंडल एवं प्रबंध कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक का आयोजन हजूरी समाज सेवा सदन में रखी गई। जिसमें संरक्षक मंडल एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में महासचिव नारायण सिंह पाऊं ने बैठक की प्रस्तावना प्रस्तुत की व कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने विगत 6 माह का वित का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष कमल सिंह भाटी ने संरक्षक मंडल का स्वागत सत्कार कर उन्हें विगत 6 माह किए गए महत्वपूर्ण कार्यो से अवगत कराया। वहीं सभी समस्त प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा समाज भवन, मुक्तिधाम, बेरा स्थल, महिषासुर मंदिर परिसर के विकास के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर संरक्षक मंडल द्वारा विगत 6 माह के कार्यकाल व वित्तीय लेखा जोखा की सराहना की गई। समाज अध्यक्ष व सभी सदस्यगणो द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर संरक्षक मंडल के सदस्य दामोदर प्रसाद तंवर, मोहनसिंह भाटी, भीखसिह भाटी, गोपीकिशन नैनसोपारा, अर्जुनसिंह सिसोदिया, श्यामसिंह देवड़ा, घनश्यामसिंह राड, दामोदरसिंह चौहान, भैरूसिंह महेचा, हेमसिंह महेचा, घनश्याम सिंह उदावत, सुजानसिंह चौहान, पुरुषोत्तम सिंह सहित प्रबंध कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष भंवरसिंह महेचा, राजेंद्रसिंह भाटी, हेमसिंह राठौड़, संगठन मंत्री रमनसिंह भाटी, सहसचिव गणपत सिंह सोलंकी, सह कोषाध्यक्ष दलपतसिंह पंवार, कार्यकारिणी के सदस्य कमलसिंह चौहान, महेंद्रसिंह तंवर, विकमसिंह भाटी, चद्रवीर सिंह पंवार, प्रेमसिंह चौहान, प्रेमसिंह राठौड़, प्रेमसिंह सोलंकी, तनेराव सिंह रामाणी, अजयपाल सिंह भाटी, रणजीत सिंह सिसोदिया, राहुलसिंह राठौड़, रघुवीर सिंह, रणजीत सिंह भाटी, शैतानसिंह, गजेंद्रसिंह तंवर, दलपत सिंह पाऊं सहित अन्य उपस्थित रहे।

सभापति कल्ला ने किया षिविर का निरीक्षण, लाभार्थियों से किया संवाद

जैसलमेर। राज्य सरकार द्वारा आमजन को योजनाओं का लाभ देने एवं शहरी क्षेत्र की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के लिए नगर परिषद जैसलमेर में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान महंगाई राहत केम्प वार्ड वासियों के लिए उपयोगी साबित हो रहे है, वहीं लोगों में योजनाओं का लाभ पाने के लिए होड सी लगी हुई है एवं शिविरों के प्रति उत्साह दिखाई दे रही है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 व 24 के लिए बिसानी पंचायत भवन में आयोजित महंगाई राहत केम्प का नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने अवलोकन किया एवं वहां कार्मिकों द्वारा निपटाए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने केम्प में लाभार्थियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में करवाए जा रहे पंजीयन की भी जानकारी ली एवं लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं में मिल रहे लाभ की भी चर्चा की तथा कहा कि वे सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने केम्प के दौरान लाभार्थियों को योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी प्रदान किए। शिविर प्रभारी एवं सहायक अभियंता हंसराज ने बताया कि केम्प में विभिन्न योजनाओं के तहत 75 परिवारों का पंजीयन किया जाकर उनकों मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान कर राहत पहुंचाई गई। शिविर में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोविंद भार्गव, सरपंच कपूरिया गणेश सुधा, पूर्व अध्यक्ष सुमार खान, पार्षद पवन सुदा,पार्षद दुर्गेश आचार्य ने भी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। वहीं उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में पंजीयन करवाने के लिए भी प्रेरित किया व शिविर को सफल बनाने में सहयोग भी प्रदान किया।

वार्ड नंबर 21 व 22 सोनाराम की ढाणी में लगे मंहगाई राहत कैंप

जिले में आयोजित किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन का उत्साह देखने को मिल रहा है। वॉर्ड नंबर 21 व 22 के लिए सोनाराम की ढ़ाणी में आयोजित हुआ षिविर वार्ड वासियों के लिए लाभदायी रहा। शिविर में जहां लाभार्थियों को मौके पर सरकार की जनकल्याणाकारी योजनाओं का लाभ मिला वहीं स्थानीय समस्याओं का भी मौके पर निस्तारण हुआ। शिविर प्रभारी एवं सहायक अभियंता हंसराज ने बताया कि केम्प में बुधवार को विभिन्न योजनाओं के तहत 42 परिवारों का पंजीयन किया जाकर उनकों मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए गए।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय...

देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अनुष्ठानपूर्वक इसका उद्घाटन किया। निश्चित रूप से देश के लोकतांत्रिक इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण पल है। हालांकि पुराने संसद भवन की भी अपनी अहमियत है और रहेगी। वह देश की लोकतांत्रिक यात्रा के संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण ही नहीं, गौरवपूर्ण पलों का भी साक्षी रहा है। आजादी के बाद देश की पहली सरकार के गठन और उसके कामकाज की बात हो या आपातकाल के रूप में लोकतंत्र पर पहले बड़े आघात की या फिर उस हमले को नाकाम करते जनादेश की। हम हर चुनौती से और मजबूत होकर निकलते रहे और हमारा वह संसद भवन हमारी लोकतांत्रिक आभा से चमकता रहा। लेकिन कोई भी समाज और राष्ट्र नए और पुराने के अनवरत मेल से ही आगे बढ़ता है। लगभग एक सदी तक मरम्मत और विस्तार से काम चल गया, लेकिन धीरे–धीरे यह भी स्पष्ट हो गया कि अब सर्वथा नई इमारत की जरूरत है। उस लिहाज से कोविड जैसी प्रतिकूलताओं के बीच जितनी कम अवधि में यह पूरी इमारत तैयार कर ली गई, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हालांकि यह सच है कि इसके निर्माण के समय और तरीके को लेकर शुरू से ही असहमतियां भी रहीं, लेकिन एक जीवित लोकतंत्र में यह कोई अनोखी बात नहीं है। उद्घाटन समारोह से जुड़े कई पहलुओं पर भी हमें अलग – अलग तरह की राय और टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं जो आगे भी चलती रहेंगी। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और इसे उसी रूप में लेने की जरूरत है। हां, एक बात जरूर खटकने वाली रही कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर विपक्ष की मौजूदगी नाम मात्र की ही रही। लगभग समूचे विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के कारणों से सहमति – असहमति हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे कारण समय रहते दूर नहीं किए जा सके, बल्कि उन्हें दूर करने की कोई गंभीर पहल भी दोनों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं दिखी। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि तमाम मतभेदों और असहमतियों के होते हुए भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व जरूरत पड़ने पर उनसे ऊपर उठने की क्षमता रखता है। ऐसे हर मौके पर उसने यह बात साबित भी की है। यह संभवतः पहला ऐसा बड़ा मौका है जिसमें दुनिया के सामने हमारे लोकतंत्र का विपक्षहीन चेहरा दिखा। हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि जो तस्वीर दुनिया के सामने गई वह हकीकत नहीं है। उद्घाटन समारोह में भले ही विपक्ष न दिखा हो, मगर देश में उसकी मजबूत उपस्थिति बनी हुई है। और देखा जाए तो उद्घाटन समारोह से उसकी अनुपस्थिति भी उसके विरोध को और प्रकारांतर से हमारे लोकतंत्र की जिजीविषा को ही रेखांकित कर रही थी। लेकिन फिर भी एक अहम मौके पर विश्व के सामने अपनी एकजुट और संपूर्ण छवि पेश करने में हमारी नाकामी पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चिंता और चिंतन की बात होनी चाहिए।

ओम 'जी' बिस्सा
प्रधान सम्पादक

'स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउन्स 2022-23' रिलीज

2025-26 तक सतही जल आधारित होगी 90 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति : अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि 2025–26 में प्रदेश के 1 करोड़ 7 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 75 प्रतिशत योजनाओं में सतही स्त्रोतों की उपलब्धता है। जल जीवन मिशन के तहत समस्त परियोजनाएं पूरी होने पर 2025 के अंत तक राजस्थान में 90 फीसदी पेयजल सतही स्त्रोतों से उपलब्ध होने लगेगा और भूजल पर निर्भरता 10 फीसदी रह जाएगी। डॉ. अग्रवाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के रसायनज्ञों की राज्य स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉ. अग्रवाल ने स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउन्स ऑफ राजस्थान 2022 – 23 भी रिलीज की। उन्होंने कहा कि 23 हजार करोड़ रूपए की सतही जल आधारित पांच बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंगलवार को आयोजित एसएलएसएससी की बैठक में मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन के तहत मंजूर इन वृहद परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत जबकि केन्द्र की 40 प्रतिशत होगी। इन परियोजनाओं के पूरी होने के बाद प्रदेश के 11 जिलों के 5739 गांव भूजल से सतही जल आधारित योजनाओं पर आ जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन में केन्द्र एवं राज्य सरकारों का उद्देश्य हर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचाना है। मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने के लिए मौजूदा 130 करोड़ लीटर जल की जरूरत बढ़कर इसकी तीन गुना हो जाएगी।

2025 – 26 तक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के साथ ही उपयोग में लिए गए पानी के लिए सही ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना भी चुनौती होगी। उन्होंने पानी के उपयोग की आवश्यकताओं को सीमित करने, वाटर रिसाइकल, रियूज एवं वेस्ट वाटर डिस्पोजल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल ने पानी की गुणवत्ता को लेकर रियल टाइम डेटा संग्रहण का सुझाव दिया ताकि स्टेटस रिपोर्ट के प्रकाशन की बजाय संग्रहित डेटा सीधे ही इस्तेमाल किया जा सके। यूनिसेफ की स्टेट हैड इजाबेल बर्डम ने कहा कि सभी के पीने योग्य जल की उपलब्धता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आधुनिक तकनीक के साथ ही परंपरागत जल संचय प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि कार्यशाला के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के संबंध में भविष्य में आवश्यक कदम उठाने का रोडमैप तैयार हो सकेगा। कार्यशाला में मुख्य अभियंता (शहरी) के. डी. गुप्ता ने कहा कि भूजल स्तर लगातार तेजी से गिर रहा है। ऐसे में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित पेयजल योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वाटर क्वालिटी पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट का लाभ फील्ड अभियंताओं, रसायनज्ञों एवं अरबन प्लानिंग से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा। कार्यक्रम की शुरूआत में स्टेटस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्य रसायनज्ञ एचएस देवन्दा ने बताया कि प्रदेश के 235 शहरी क्षेत्रों का सर्वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किया गया है। 89 कस्बों में पेयजल आपूर्ति सतही जल स्त्रोतों से, 70 में सतही एवं भूजल दोनों से तथा 76 कस्बों में सिर्फ भूजल आधारित है। उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त 33 प्रयोगशालाएं एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त हैं। इन प्रयोगशालाओं के एनएबीएल सर्टिफिकेशन की निरंतरता के लिए यूनिसेफ एवं नीरी के सहयोग से समय – समय पर रसायनज्ञों एवं अन्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में आए पीएचईडी के पूर्व मुख्य रसायनज्ञ एसएस ढिंढसा ने पानी की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करने के विभाग के कदम की सराहना की। यूनिसेफ के वॉश अधिकारी नानक संतदासानी ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में यूनिसेफ की ओर से पीएचईडी को तकनीकी सहयोग दिया गया।

प्रदेश में तम्बाकू फ्री यूथ कैम्पेन का हुआ शुभारम्भ

जयपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, 31 मई के उपलक्ष्य में झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर में तम्बाकू फ्री यूथ कैम्पेन का शुभारम्भ किया गया, साथ ही तम्बाकू निषेध विषय से जुड़े पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2022–23 में तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं अजमेर जिलों की तम्बाकू नियंत्रण इकाइयों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि तम्बाकू मुक्ति का यह अभियान निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु संचालित की जाने वाली 60 दिवसीय कार्ययोजना में शिक्षा, स्थानीय ग्रामीण एवं शैक्षणिक निकायों के साथ विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने इस कार्ययोजना के दौरान प्रदेश में शहरी व ग्रामीण वार्ड, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए प्रतियोगिता आयोजन जैसे नवाचार संचालित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेन्द्र सोनी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने एवं जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से तम्बाकू मुक्ति का प्रस्ताव करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर चालान कार्यवाही महज प्रतीकात्मक न रहे बल्कि संदेशात्मक होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने पर भी जोर दिया। निदेशक जन–स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में निदेशक आरसीएच डॉ. आरपी डोरिया, संयुक्त निदेशक तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ डॉ. एसएन धौलपुरिया ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। फील्ड स्तर पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम एवं आशा सहयोगिनियों भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रदेश में निर्माण कार्यों की बढ़ेगी रफ्तार

पीडब्ल्यूडी और संवेदकों के बीच बनी सहमति, निविदाओं में लेंगे भाग

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में बुधवार को विभाग के स्तर पर यूनाइटेड कांट्रेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के साथ सहमति बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा च्ॅक् की निविदाओं में भाग लेने का निर्णय किया गया। बैठक में जाटव द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स की समम्स्याओं जिसमे जुलाई 2022 में जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बढ़ने से कॉन्ट्रैक्टर्स पर बढे हुए वित्तीय भार के विरुद्ध अतिरिक्त भुगतान करने, कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लासिफिकेशन ए, बी, सी, डी आदि की वित्तीय सीमा बढ़ाने, टाइम एक्सटेंशन के प्रकरणों में फील्ड कार्यालयों को अधिक शक्तियां देने और जिन निविदाओं में पर्याप्त आवेदन नहीं हुए है उनमे आरटीपीपी नियम 68 के तहत परिक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वाशन दिया गया। उपरोक्त आश्वासन के उपरांत संवेदकों की ओर से बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा की गयी। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पीडब्लूडी वैभव गालरिया, मुख्य अभियंता संजीव माथुर और संवेदकों की तरफ से एसोसिएशन अध्यक्ष बीएस. राव, इंद्रजीत टांक, नारायणराम डाबड़ी, किरोड़ीमल मोदी, रतनलाल विश्नोई व अंजन कुमार चौधरी शामिल हुए।

महंगाई राहत कैम्प; 6.19 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड हो चुके जारी

1.37 करोड़ से ज्यादा परिवार हुए लाभान्वित

जयपुर। प्रदेश के हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किये जा रहे महंगाई राहत कैम्प हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। कैम्पों में रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ प्राप्त कर आमजन राहत महसूस कर रहे हैं। बुधवार शाम तक कैम्पों में 6.19 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, जबकि 1.37 करोड़ से ज्यादा परिवार अब तक इन कैम्पों से लाभान्वित हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम तक इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 47 लाख, मुख्यमंत्री निशुल्क घरेलू बिजली योजना में 78.28 लाख, मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना में 9 लाख, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 87.67 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 54.84 लाख एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4.04 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 43.75 लाख, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 80.09 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1.07 करोड़ एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 1.07 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं।

मुख्यमंत्री से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जयपुर में 5 लाख से ज्यादा परिवारों ने करवाया कामधेनु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन

जयपुर। पिछले साल लंपी बीमारी बेजुबान गौवंश के लिए कहर साबित हुई थी। राजस्थान के पशुपालकों को दुधारू पशुओं की असामयिक मौत होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के पशुपालकों को प्रति परिवार दो गाय एवं भैंसों के लिए 40–40 हजार का बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर में आयोजित महंगाई राहत कैंप में 5 लाख से ज्यादा परिवारों ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

बुधवार को वितरित किये गए 76 हजार से ज्यादा गारंटी कार्ड

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि बुधवार को 76 हजार 949 गारंटी कार्ड जारी किये गए। जिसमें से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 11 हजार 63, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 15 हजार 783, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 15 हजार 783, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 1 हजार 57, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 8 हजार 502 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 14 हजार 424, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2 हजार 629, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 4 हजार 456, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 3 हजार 81, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 171 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, प्रत्येक गरीब परिवार का उत्थान राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का ही परिणाम है कि आज राज्य में 96 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं तथा मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही राज्य सरकार का ध्येय है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों से आने वाली महिलाओं से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिला और आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम एकजुट हैं यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की दूरदर्शिता के चलते आज महिलाओं को सत्ता में भागीदारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी का जीवन महिला सशक्तिकरण का एक बेमिसाल उदाहरण है। इस दौरान गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाएं अतुलनीय

महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी तथा महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जैन, सिख, मुस्लिम तथा ईसाई समुदाय के विभिन्न संगठनों की महिला प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं अतुलनीय हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आज की बुनियादी जरूरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। राजस्थान देश का पहला घ्सा राज्य है जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उड़ान योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने का लिया संकल्प

महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों द्वारा मिल रही राहत सराहनीय है। निःशुल्क बिजली योजना तथा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है तथा लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति पर सुझावों का आदान–प्रदान भी हुआ।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आएगी भारत निर्वाचन आयोग की टीम

जयपुर। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम जून माह में दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम 15 और 16 जून को जयपुर आएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की यह टीम मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। गुप्ता ने बताया कि इस दौरान यह टीम जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगी। साथ ही चुनाव में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसियों एवं विभागों, इनकम टैक्स , नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आबकारी, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), रेलवे पुलिस बल, सीआईएसफ तथा वाणिज्य कर विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। जिलों में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का कार्य 5 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जगह 11 जून से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा और मतदान और उससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

Created by Universal Document Converter

बृजभूषण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, सबूत नहीं होने की खबर गलत

एजेंसी

दिल्ली। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों की मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अब तक पुलिस को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सहायक सबूत नहीं मिले हैं। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के पास पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है।

दिल्ली पुलिस का खंडन

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छपी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ मीडिया चैनल महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकद्दमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। यह खबर पूरी तरह गलत है। यह केस अभी विवेचन में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जायेगी।

नहीं मिले पुख्ता सबूत

मीडिया सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में जोड़े गए पीओसीएसओ की धाराओं में सात साल से कम के कारावास की सजा है। इसलिए जांच अधिकारी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बृजभूषण सिंह किसी भी तरह ना तो गवाहों को प्रभावित कर रहा है और न ही सबूत नष्ट कर रहा है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की है। इसमें एक एफआईआर नाबालिग से यौन शोषण को लेकर है, जिसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है जबकि दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है।

महिला आयोग का नोटिस

उधर, दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में डीसीपी, नई दिल्ली को समन जारी किया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले एक शख्स ने खुद को नाबालिग लड़की का चाचा बताकर उससे जुड़े कागजात प्रेस के सामने रखे थे। इसमें उस शख्स ने दावा किया था कि आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग नहीं है।

भोपाल नगर निगम की नर्सरी में गाड़ियों से निकाला जा रहा डीजल, वीडियो वायरल

एजेंसी

भोपाल। नगर निगम की पुराने मछली घर के पास स्थित नर्सरी में डीजल चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी निगम की गाड़ी से डीजल निकालकर कुप्पे में भरता नजर आ रहा है। इस तरह डीजल चोरी कर बेचा जा रहा है। यही नहीं, डीजल चोरी के अलावा निगम के अस्थायी कर्मियों द्वारा यहां रखे डस्टबिन तोड़कर इन्हें कबाड़ में बेचने की खबरें भी आई है। दरअसल इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने उपलब्ध कराया। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि यह काम एएचओ झील राजेश कुरील की मिलीभगत से हो रहा है। कुरील द्वारा इसके जरिए रोजाना डीजल बेचकर मोटी कमाई की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में निगम आयुक्त केवीएस चौधरी को वीडियो उपलब्ध कराते हुए शिकायत की बात भी कही है। बता दें कि इससे पहले भी नगर निगम की गाडियों से डीजल चोरी के वीडियो आए है जिसके बाद कार्रवाई की गई है। इसके अलावा निगम ने इस चोरी से बचने के लिए कई सारी गाडियों को डीजल की बजाए सीएनजी में परिवर्तित किया है। उधर, झील संरक्षण विभाग में कार्यरत ललित विजयवर्गीय इन गाडियों के इंडेन वितरित करता है। सूत्र बताते है कि प्रत्येक इंडेन बुक जारी करने पर 300 रूपए ललित विजयवर्गीय को दिए जाते है। इसके बाद ही ड्राइवर को डीजल लेने के लिए इंडेन जारी होता है।

किलोल पार्क नर्सरी में भी होती है डीजल चोरी

उधर, मछली घर के अलावा किलोल पार्क स्थित नर्सरी में भी झील संरक्षण की बड़ी गाडियों से डीजल चोरी करने के आरोप लगे है। कर्मचारियों का एक धड़ा नाम न छापने की शर्त पर बताता है कि शहर के सेंट्रल वर्ज पर लगे पौधों को पानी का छिड़काव करने के लिए जो ट्रालिया या टेंकर संचालित किए जा रहे है, उनके द्वारा भी हेरफेर किया जा रहा है। दरअसल इन टेंकरों को दिन में दो बार छिड़काव के लिए भेजा जाता है लेकिन ये टेंकर दिन में दो बार पानी देने की बजाए दो दिन में एक बार पानी देते हैं। इसके बदले बचे हुए डीजल को बेच दिया जाता है।

पिज्जा समय से नहीं पहुंचाने पर मिली सजा

एजेंसी

जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने पिज्जा की डिलीवरी समय पर न किए जाने के रवैये को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार प्रथा के दायरे में रखा। इसी के साथ जुबीलेंट फुड वर्क्स लिमिटेड व डोमिनोज पिज्जा को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दे दिए गए। आयोग के चेयमैन नवीन कुमार सक्सेना व मेम्बर सुषमा पटेल व अमित तिवारी ने पिज्जा का मूल्य 305 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने क आदेश दिया है। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार व मुकदमे का खर्च दो हजार रुपये भुगतान करने कहा गया है। परिवादी शिवेंद्र पांडे की ओर से अधिवक्ता शेख अकरम व सुयश प्यासी ने दलील दी कि परिवादी ने 31 दिसंबर, 2019 को रात्रि आठ बजे पिज्जा आर्डर किया था। इसके लिए 305 रुपये आनलाइन भुगतान किए गए। उसे सूचित किया गया कि नववर्ष की संध्या होने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परिवादी ने डेढ़ घंटे तक प्रतीक्षा की। इसके बाद कस्टमर केयर पर शिकायत की। उसे भरोसा दिलाया गया कि शीघ्र ही पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा शिकायत करने पर डिलीवरी पर्सन का अभाव होने का बहाना बनाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि जैसे ही डिलीवरी पर्सन आएगा पिज्जा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसीलिए पहले लीगल नोटिस भेजा गया फिर परिवाद दायर कर दिया गया।

भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है : सीए अग्रवाल

एजेंसी

बिलासपुर। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के तुलना में भारतीय बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। देश की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही जनता की आर्थिक स्थिति में अच्छी होगी। अभी निवेश करने के लिए भारतीय बाजार लाभदायक है। भारत 2023 में 3.7 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूके से आगे है। हमारी जीडीपी अभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले जीडीपी में से एक है। अनुमानित ग्रोथ रेट 6.9 प्रतिशत के लगभग है। देश में पिछले माह अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ था, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। यह देश में उपभोक्ता के खर्च को दर्शाता है और इससे देश की तरक्की में सहायक है। भारतीय शेयर बाजार पिछले दिनों ही फ्रांस के शेयर बाजार से आगे निकल गए हैं और अब दुनिया के पांचवें सबसे बड़े शेयर बाजार के स्थान पर स्थित है। पूरी दुनिया में निवेश के लिए भारत अभी सबसे आकर्षित इकानामी है। सरकारी कंपनियां व सरकारी बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनमें महारत्न कंपनियों में निवेश की संभावना तलाश सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से बाजार में नकद की आवक बढ़ेगी। इससे बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। सरकार ने इस साल के बजट में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रविधान किया है, लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कुल मांग में वृद्धि होगी।

रजत अग्रवाल, सीए बिलासपुर

सीएम बघेल ने जारी किया बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त; करीब एक लाख युवाओं के खाते में आए 32 करोड़ रुपये

एजेंसी

रायपुर। राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश के एक लाख से अधिक युवाओं के बैंक खाते में 31 मई को 32 करोड़ 35 लाख 25 हजार रुपये की राशि अंतरित की। इस महीने 24 हजार 15 युवा अतिरिक्त जुड़े हैं, जिनका आवेदन स्वीकृत किया गया है। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 66 हजार 185 युवाओं को 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रुपए की राशि अंतरित की गई थी। इस बार इन्हें दूसरी किश्त दी जा रही है। इसे मिलाकर एक लाख 5 हजार 395 युवाओं के खाते में 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रुपए की राशि अंतरित हो जाएगी। इस मौकै पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे, आज हमने अपना वादा निभाया है। विभिन्न विभागों में लगातार वैकेंसी आ रही हैं। योजना के तहत 1701 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को 33 संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिन युवाओं के खाते में राशि अंतरित की जानी है उनमें महिलाओं की संख्या 64 हजार 25 है, जो कि कुल युवाओं की संख्या का 39 प्रतिशत है। इसी तरह एख लाख 509 पुरुष हैं, जो कुल युवाओं का 61 प्रतिशत है। शहरी युवा 27 हजार 970 जो कुल युवाओं की संख्या का 17 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं की संख्या एक लाख 36 हजार 564 हैं, जो कुल युवाओं की संख्या का 83 प्रतिशत हैं।

1680 प्रकरण अपील के लिए

रोजगार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियमानुसार पात्रता जांच हो रही है। जिन मामलों में भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है। 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है। 493 प्रकरण अस्वीकृत व 1001 प्रकरण लंबित है। पोर्टल में भी आनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था दी गई है। इसमें 2942 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 1425 शिकायतें निराकृत कर दी गई है। शेष के निराकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

1701 युवाओं का प्रशिक्षण भी प्रारंभ

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन भरने के साथ ही बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण का विकल्प भी दिया जा रहा है, ताकि उन्हें नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके। अब तक 1701 युवाओं का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है। लाइवलीहुड कालेज सहित 33 संस्थानों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रांची में ईडी की छापेमारी, कांग्रेस विधायक और सहयोगियों से जुड़े 16 ठिकानों पर मारे छापे

एजेंसी

रांची। रांची में पोड़ैयाहाट (गोड्डा) से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों से जुड़े 16 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। यह छापेमारी रांची स्थित छह तथा दुमका व गोड्डा स्थित 10 ठिकानों पर सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चली। छापेमारी में ईडी को कुछ नकदी के अलावा चल – अचल संपत्ति में निवेश की जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज का ईडी सत्यापन करेगी। छापेमारी में ईडी ने प्रदीप यादव के करीबी अजय कुमार झा के दुमका स्थित ठिकाने से 60 लाख रुपये बरामद किए हैं। इसी तरह ईडी को मनोज कुमार अकेला के गोड्डा स्थित आवास से करीब पांच लाख रुपये मिले हैं। वह अभी फरार है। जानकारी के अनुसार इस कंपनी में सुचित्रा देवी भी सहयोगी हैं, जो बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह के पूर्व विधायक की पत्नी हैं। रांची में दूसरा ठिकाना शिव कुमार का है। वे रांची में 15 वर्षो तक अभियंता रहे हैं। उनका बरियातू में फायरिग रेंज के पास आवास है।

छापे में कहां से क्या मिला

ईडी की यह छापेमारी पूर्व में आयकर विभाग की छापेमारी में मिले इनपुट के आधार पर हुई है। उस वक्त आयकर विभाग की छापेमारी में विधायक प्रदीप यादव के यहां से दो लाख रुपये, उनके करीबी गोड्डा के होटल व्यवसायी श्यामाकांत यादव के यहां से 40 लाख रुपये, दुमका के विनोद कुमार लाल के यहां से नौ लाख रुपये बरामद हुए थे। विधायक प्रदीप यादव के रांची स्थित सरकारी आवास के अलावा गोड्डा स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है।

छतीसगढ़ के कोरबा में दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त भिडंत सिलेंडर फटने से एक वाहन में लगी आग

कोरबा। छतीसगढ़ के कोरबा जिले के बागो थाना अंतर्गत एनएच 130 कटघोरा – चोटिया सड़क मार्ग में भारी – भरकम वाहनों की बढ़ती संख्या एवं नौतपा की तेज तपिश के कारण अचानक वाहनों में आग लग जाने के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार की रात हुई। घटना टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है। डायल 112 की टीम को कंट्रोल सेंटर रायपुर से सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जलते वाहन में फंसे दो लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल तत्काल इलाज के लिए पोड़ी – उपरोड़ा रवाना किया गया। बताया जा रहा हैं की सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रायपुर से सूचना मिली कि बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चोटिया में दो ट्रकों की टक्कर से आग लग गई है और नेशनल हाईवे–130 में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। सूचना पर बांगो कोबरा–1 की टीम आरक्षक संजीव कंवर एवं डायल 112 के चालक नीरज पांडे, ने घटनास्थल पर तत्काल रवाना होकर कॉलर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। जहां देखा कि एक ट्रक क्रमांक सीजी 11.एवाई 6175 में भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें सवार चालक एवं परिचालक बुरी तरीके से वाहन में फंसे हुए थे। टीम ने राहगीरों की मदद से आनन – फानन में कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। वाहन चालक युवराज कुमार मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष व परिचालक शरीफ खान 23 वर्ष को पैर और कंधे पर अत्यधिक चोटे आई थी। वाहन चालक युवराज ने बताया कि एक और ट्रक के सामने से टक्कर हो गई। केबिन में रखें खाना बनाने वाले सिलेंडर के फटने से एकाएक आग पकड़ ली। टीम ने दोनों घायलों को मौके पर मौजूद हाईवे एंबुलेंस 1033 की मदद से बेहतर उपचार के लिए समय रहते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी उपरोड़ा में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। नेशनल हाईवे पर लगे जाम को भी पुलिस ने बहाल कराया।

सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने को एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता 700 लाख टन बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि देश में अनाज भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन है। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2,150 लाख टन की जाएगी। यह क्षमता सहकारी क्षेत्र में बढ़ेगी। ठाकुर ने प्रस्तावित योजना को सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम बताया। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 2,000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को संकट के समय अपनी उपज औने – पौने दाम पर बेचने से रोकना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिये परिवहन लागत कम होगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। लेकिन, मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है। बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि 3.50 करोड़ से ज्यादा मकान बनाकर गरीबों को दिए गए। वहीं 9.60 गैस सिलिंडर कनेक्शन महिलाओं को दिए गए, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए. इसके अलावा हर घर को नल से जल में 12 करोड़ कनेक्शन लगाए गए, 60 करोड़ लोगों को इलाज की व्यवस्था की।

बंम महादेव टी स्टॉल

हनुमान चौराहा, जैसलमेर

पर्यटन नगरी में गुणवतापूर्ण मसालेदार एवं शुद्ध चाय, कॉफी तथा गरमा गरम दूध मिलने का एकमात्र स्थान

– मनोहरलाल आचार्य

Created by Universal Document Converter

जैसलमेर जिले में मेघ गर्जन और तेज अंधड़ में सावधानी बरतने की अपील

जैसलमेर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी सहायता गोपाल लाल स्वर्णकार ने आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग तथा मौसम विभाग के पुर्वानुमान अनुसार जैसलमेर जिले में आंधी तुफान के साथ मेघ गर्जन रहने की संभावना होने से संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में अलर्ट रहने एवं आमजन से भी तेज अंधड़ व मेघ गर्जन के दौरान घरो के अन्दर रहने,बड़े पेड़ो के नीचें खड़े ना होने,कच्ची दीवार के पास खड़े ना होने,अंधड़ के दौरान खुले मैदान में होने पर नीचे लेट जाने,पशुओं को पेड़ से ना बांधने,घर में बिजली के उपकरणों का सम्पर्क हटा देने, बिजली के खम्भों के नीचे व पास दुपहिया और चार पहिया वाहन खड़ा ना करने,जिन घरों में टीन शैड हैं उनके गेट बन्द रखने, बड़े होर्डिंग्स लगे स्थानों से दूर रहने की अपील की है साथ ही उन्होंने विद्युत खम्भों, तारों व ट्रांसफार्मर आदि से पर्याप्त दूरी बनाये रखने तथा नजदीकी सुरक्षित स्थलों पर आश्रय लेने और सावधानी बरतने की अपील की है।

सरहद के गांवों के विकास को दी जाएगी प्रथम प्राथमिकता : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

जैसलमेर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सरहद के तनोट क्षेत्र के घंटियाली मंदिर के पास वंदे सरहद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्राण कार्यक्रम का आगाज किया। जोशी ने अपने वक्तव्य में गहलोत सरकार पर केंद्र की योजनाओं को अपना बता कर लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार किसानों को कर्ज माफी व बेरोजगारों को भत्ता देने के झूठे वादे पर सत्ता में आई है। इस कार्यक्रम से पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, महामंत्री भजनलाल शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया प्रभारी बाबूलाल शर्मा ने बताया के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, महामंत्री सवाई सिंह गोगली, राष्ट्रीय युवा मोर्चा सदस्य आईदान सिंह भाटी, मंत्री कवराज सिंह चौहान, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष उदयसिंह भाटी, कोषाध्यक्ष हुकमाराम कुमावत, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष चंदनसिंह हेमा, वीरेंद्रसिंह सोलंकी, जिला प्रमुख प्रतापसिंह सोलंकी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष कादर बक्स, प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन खान, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, छोटूसिंह भाटी, शैतानसिंह राठौड़,, सुरेंद्र सिंह, हाथीसिंह मुलाना, पवन कुमार सिंह सहित सभी मण्डल अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम में सहयोग के लिए विरेंद्र सिंह सोलंकी व हुकमाराम कुमावत का धन्यवाद ज्ञापित किया साथ ही गजरूप सागर महंत बालभारती का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई; खाद्य नमूने लेकर 1893 लीटर घी किया सीज

जैसलमेर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्त नकाते शिवप्रसाद मदन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य पदार्थो के सैंपल लिए जा रहे है। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी. एल. बुनकर के मार्गदर्शन में जैसलमेर शहर में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मैसर्स अनिल एजेंसी, ढिब्बा पाड़ा पर कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि घी दावत व मिल्को ब्रांड के नमूने जांच के लिए एफएसएसए एक्ट के तहत संग्रहित किए गए तथा मिलावट का संदेह होने पर लगभग 1 हजार 893 लीटर घी जब्त किया गया। जैसलमेर शहर से दो देसी घी एवं दो फ्रूट ड्रिंक के कुल चार खाद्य पदार्थो के नमूने भी लिए गए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा एवं प्रवीण चौधरी की टीम ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया।

श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 13 से

जैसलमेर।'मां लटियाल शक्तिपीठ जोधपुर की पीठाधीश संत तारा देवी के श्रीमुख से श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन स्थानीय माहेश्वरी वृद्धा आश्रम कलाकार कॉलोनी जैसलमेर में आगामी 13 जून से 19 जून के मध्य होगा। कथा दोपहर 3.30 से 6.30 शाम तक होगी। आयोजन के मीडिया प्रभारी प्रमोद जगानी ने बताया कि संत तारा देवी द्वारा जैसलमेर शहर में यह पहली बार कथा होगी। मूल रूप से फलोदी की निवासी संत तारा देवी अनेकों धार्मिक अनुष्ठानों की ज्ञाता है। साथ ही उनके नेतृत्व में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान एवं कथाएं पूर्व में देश के कई हिस्सों में की गई हैं। जैसलमेर शहर में श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ के साथ श्री लक्ष्मी यज्ञ उनके द्वारा किया जा रहा है। जगानी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में उनके हजारों अनुयाई है। ऐसे संत की वाणी सुनना हम सभी का सौभाग्य होगा। उन्होंने आयोजकों की ओर से सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में रसिक श्रोता, कथा एवं यज्ञ का लाभ ले।

छः दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम 30 मई से प्रारंभ

जैसलमेर। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जैसलमेर द्वारा हैप्पीनेस प्रोग्राम 30 मई से भाटिया बगीची के पीछे प्राची क्लीनिक में सुबह 6 से 8 बजे आयोजित किया जा रहा है। मुख्य शिक्षिका अंजू गर्ग ने बताया कि इस छः दिवसीय प्रोग्राम में विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन क्रिया सिखाई जा रही है। हैप्पीनेस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में साधारण व्यक्ति की खोई हुई प्रसन्नता को फिर से जागृत करना व तनाव मुक्त, शांत एवं प्रसन्न करना है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये संपर्क कर सकते हैं।

प्रभु टी स्टाल

हनुमान चौराहा, जैसलमेर

पर्यटन नगरी में गुणवतापूर्ण मसालेदार एवं शुद्ध चाय, कॉफी तथा गरमा गरम दूध मिलने का एकमात्र स्थान

- सांगाराम चौधरी

ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर संपन्न

जैसलमेर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है : जिला प्रमुख प्रतापसिंह

जिला संवाददाता

जैसलमेर। राज्य क्रिकेट संघ के निर्देशानुसार जैसलमेर में 15 मई से आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रताप सिंह रहे। वहीं अध्यक्षता युवा नेता कंवराज सिंह चौहान ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकपाल योगेश गज्जा व आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष विमल शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसलमेर में प्रतिभाओं की कमी नही है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके है। उन्होंने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि योगेश गज्जा ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविर में भारी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नही है। कड़ी मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता कंवराज सिंह ने कहा कि खेलने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है भाईचारा और मेल जोल भी बढ़ता है। खिलाड़ी नियमित अभ्यास से सफलता हासिल कर सकते है। इस अवसर पर शिविर में भाग ले रहे 100 से अधिक खिलाड़ियों को टीशर्ट व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन विक्रम चुरा ने किया। शिविर प्रभारी कृष्ण गोपाल सोनी, सह प्रभारी विनर शर्मा, प्रशिक्षक राजेश कुमार, विजय वैष्णव, नरपत चौधरी, पुष्पेंद्र बोहरा को भी प्रमाण पत्र व टी शर्ट प्रदान किए गए। समारोह के अंत में आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में नरेश भाटिया, शिवदान राम, रमेश तंवर, श्रीवल्लभ बिस्सा, चन्दनदान सहित अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रताप सिंह, युवा नेता कंवराज सिंह व लोकपाल योगेश गज्जा ने क्रिकेट मैदान में पौधरोपण किया तथा मूक पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा कबूतरों को दाना डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी व क्रिकेट संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

पाक विस्थापितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन

जैसलमेर। पाक विस्थापितों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी के अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ अभियंता विभाग, सीडीईओ, सीएमएचओ, जिला उद्योग अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पोकरण, आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर, सचिव यूआईटी, व जोधपुर से प्रतिनिधि सीमांत लोक संगठन समिति के सदस्य रहेंगे। एडीएम जैसलमेर को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही एडीएम समिति की प्रत्येक माह में बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

वार्ड नंबर 23 व 24 बिसानी भवन में लगे मंहगाई राहत कैंप का बीसूका उपाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर ने किया निरीक्षण

जैसलमेर। राज्य सरकार की विशेष पहल पर जिले में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन का उत्साह देखने को मिल रहा है। वॉर्ड नंबर 23 व 24 बिसानी भवन पंचायत के मंहगाई राहत कैंप में बीसूका उपाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने लाभार्थियों से संवाद कर कैंप की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया और समस्त योजनाओं की जानकारी दी। लाभर्थियों को लाभार्थी कार्ड वितरण किए गए, योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर प्रभारी एवं सहायक अभियंता हंसराज ने बताया कि केम्प में विभिन्न योजनाओं के तहत 48 परिवारों का पंजीयन किया जाकर उनकों मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान कर राहत पहुंचाई गई। शिविर में समाजसेवी गोविंद भार्गव, सरपंच कपूरिया गणेश सूदा, पूर्व अध्यक्ष सुमार खान, पार्षद पवन सुदा, पार्षद दुर्गेश आचार्य ने भी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। वहीं उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में पंजीयन करवाने के लिए भी प्रेरित किया व षिविर को सफल बनाने में सहयोग भी प्रदान किया। इसके साथ ही नगर परिषद के कार्मिकों एवं अन्य विभाग के कार्मिकों द्वारा वार्डवासियों के कामों को निस्तारित किया।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण

जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जालूवाला में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत गारंटी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य की जनकल्याणकारी सरकार द्वारा आमजन के हितार्थ विभिन्न अभियान योजनाओं एवं फैसलों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी पात्र से राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा इन्दिरा गांध ी गैस सब्सिडी योजना में पंजीयन करवाकर महंगाई से राहत प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग एवं शहरों के संग अभियानों में भी आमजन अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों के सम्बन्धित कार्यो को करवा सकता है। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन के कार्यों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत होने वाले लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण भी किया। इस दौरान सम्बन्धित शिविर प्रभारी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

डूंगरपुर शील्ड खेलने जैसलमेर की टीम रवाना

जैसलमेर। जयपुर में 5 जून से आयोजित होने वाली डुंगरपुर शील्ड किक्रेट प्रतियोगिता (19 वर्ष) में भाग लेने के लिए बुधवार को जयपुर के लिए रवाना हो गई है टीम का कप्तान भुवन शर्मा को तथा उप कप्तान गुलाब सिंह को बनाया गया है जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल शर्मा ने बताया की जिला क्रिकेट संघ के चयनकर्ताओं विक्रम चुरा ललित शर्मा तथा विजय वैष्णव ने टीम का चयन किया है। टीम में भुवन शर्मा (कप्तान), गुलाब सिंह उपकप्तान, जयंत माली संजय माली सिद्धार्थ पुरोहित, रामदेव चौधरी, जसवंत सुथार, अशोक कुमार, मोहम्मद असलम, रोहित सोलंकी,भरत कुमार, रमेश कुमार,ओरेनद सिंह लक्षित लूणावत जतिन सैनी व भरत चारण को शामिल किया गया है टीम के मुख्य कोच राजेश कुमार सहायक कोच नरपत चौधरी तथा मेनेजर विनर शर्मा को बनाया गया

शहर में सत्यम क्लासेज का हुआ शुभारंभ

जैसलमेर। शहर के ढिब्बा पाडा मे स्थित सत्यम क्लासेस का शुभारंभ मुख्य अतिथि महारावल चैतन्यराज सिंह एवं नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के संचालकों लोकेश सोनी, सुधा पुरोहित एवं सुदीप व्यास को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। संचालकों ने बताया कि यह क्लासेज उन विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित होगा जो वास्तविक रूप में शिक्षा हासिल कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते है परंतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। क्योंकि संस्था का स्लोगन है शिक्षा एक अनमोल रत्न है, जिसे सब तक पहुंचाना हमारा प्रयत्न है।

कमला नेहरू उच्च प्राथमिक विद्यालय

शास्त्री कालोनी (गफूर भट्टा), जैसलमेर 345001

(शिक्षा विभाग से स्थाई मान्यता प्राप्त)

स्वर्णनगरी जैसलमेर में वर्ष 1988 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था

सत्र 2023-24 के लिए कक्षा बालघर से अष्टम तक **प्रवेश प्रारम्भ**

संस्था की विशेषताएँ:–

1. योग्य, अनुभवी एवं सीनियर शिक्षक वर्ग द्वारा अध्यापन कार्य ।
2. स्वानुशासन, शिष्टाचार, व्यवहारिकता व भारतीय सभ्यता व संस्कृति जैसे गुणों का विकास ।
3. उचित एवं पूर्ण सुरक्षित विद्यालय भवन ।
4. पर्याप्त, सुरक्षित एवं साफ - सुथरा खेल मैदान ।
5. शिक्षण के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां ।
6. बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन ।
7. सीसीटीवी कैमरा युक्त विद्यालय भवन ।
8. उचिताकार के कक्षा - कक्ष ।
9. शुद्ध व शीतल पेयजल हेतू आरओ व वॉटर कूलर की व्यवस्था ।
10. नन्हें - मुन्हों के लिए झूले व फिसलन पट्टी ।

"बालक - बालिका का सर्वांगीण विकास ही हमारा और आपका लक्ष्य है, आईये आप और हम एकजुट होकर इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें।"

:: सम्पर्क ::
कमला नेहरू संस्थान
संचालन समिति
शास्त्री कालोनी, जैसलमेर

स्वात्वाधिकारी, मालिक, प्रकाशक, सम्पादक एवं मुद्रक : श्री ओम जी द्वारा स्वास्तिक ऑफसेट, कलाकार कॉलोनी, जैसलमेर से मुद्रित एवं नथमल की हवेली के सामने, गोयदानी पाड़ा, जैसलमेर से प्रकाशित। फोन : 02992-250426, मो. : 9414149426, E-mail : omgbissa@gmail.com

Created by Universal Document Converter